PUNE RESEARCH SCHOLAR ISSN 2455-314X
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL VOL 6, ISSUE I

वर्तमान भारत के संदर्भ में शाश्वत विकास की अवधारणा के महत्व का विवेचनात्मक अध्ययन

डॉ. आर. एच. नगरकर

सहयोगी प्राध्यापक

जी. एस. कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकॉनॉमिक्स

नागपूर (महाराष्ट्र) भारत.

सारांश :—

शाश्वत विकास वह है जो सतत बना रहे, वर्तमान काल से भविष्यकाल तक अनंत बना रहे। वर्तमान पीढी विकास के लिए प्राकृतिक—भौतिक संसाधनों का उपयोग करती है। यह उपयोग विवेकशील रुप से होना चाहिए। जिससे ये संसाधन आनेवाली पीढी को पर्याप्त रुप में हस्तांतरीत किए जा सके। वर्तमान में भी एक बेहतर पर्यावरण बनाने का प्रयत्न हो और भावी पीढी के लिए भी बेहतर पर्यावरण सौपा जा सके। आर्थिक विकास निश्चित रुप में प्राकृतिक संसाधनों का ऱ्हास, प्रदूषण वृध्दि, पर्यावरण को क्षति पहूचाता है। शाश्वत विकास बनाए रखते के लिए आज भारत के समक्ष अनेक चूनौतियॉ है। किंतू इन चूनौतियों से निपटने के समाधान भी उपलब्ध है, सरकार और जनसहभाग से ही यह संभव होगा। शाश्वत विकास के साथ पर्यावरणीय संरक्षण को जनआंदोलन बनाना होगा। शाश्वत विकास की अवधारणा के महत्व को वर्तमान में समझना आवश्यक है ।

मुलशब्द :— आर्थिक विकास, शाश्वत विकास, पर्यावरण रक्षण, वर्तमान पीढी, भावी पीढी, प्राकृतिक पूंजी, प्राकृतिक संपदा, सरकारी प्रयास, लोक सहभाग, कडे कानून व अनुपालन, सामूहिक दायित्व,

प्रस्तावना :—

विश्व, देश अथवा समाज हो इसका केन्द्रबिंदू मानव है। मानव ने अपने आरंभ काल से ही निरंतर परिवर्तनों का सामना किया है। वह स्वयं भी परिवर्तनशील है,

प्रत्येक बदलावों में ढल जाने की उसमें सहज प्रवृत्ति है। अपने आसपास के वातावरण को अपने अनुसार ढालने की क्षमता और सामर्थ्य भी मनूष्य में है। इसी प्रवृत्ति और सामर्थ्य ने उसमें विकास करने का गुण उपजाया है। निरंतर विकास करना चाहे स्वंय का हो, वो सामाजिक या आर्थिक विकास हो, इसके लिए संपूर्ण मनुष्य जाति ने अविरत प्रयत्न किए है और ये निरंतर जारी भी है। इस विकास के क्रम में आर्थिक विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा अनुभव होता है कि किसी भी राष्ट्र में आर्थिक विकास का ही अनन्यसाधारण महत्व है। प्रतयेक देश की सरकार अपने समस्त नागरिकों सहीत आर्थिक विकास और आर्थिक वृध्दि के लिए प्रयास करती है, किंतू इस आर्थिक विकास की शर्त होनी चाहिए, बिना पर्यावरण को क्षति पहुचाए विकास, यदि विकास की होड और दौड में पर्यावरण को क्षति पहुचती है तो ऐसा विकास बेमानी हो जायेगा। यदि पर्यावरण ही न बचा तो मानव जाति भी बच नही पायेगी। विकास के सामने एक बडी चूनौति है पर्यावरण सरंक्षण। देखा ये जाता है विकास की अंधी दौड में पर्यावरण की उपेक्षा हो जाती है। आवश्यकता है विकास भी हो और पर्यावरण सरंक्षण भी हो। तभी ऐसे विकास को हम शाश्वत विकास कहेंगें ।

उद्देश :—

१) शाश्वत विकास की अर्थअवधारणा का अध्ययन करना ।
२) शाश्वत विकास के महत्व का अध्ययन करना ।
३) शाश्वत विकास के समक्ष वर्तमान स्थिती और चूनौतियों का अवलोकन करना।
४) समाधान की उपाययोजना का अध्ययन

शाश्वत विकास की आवश्यकता :—

विकास की गति बढती है तो प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक दोहन होने लगता है, साथ में निर्माण होती है, पर्यावरण को क्षति पहूचने की निश्चित संभावना। प्राकृतिक संसाधन हमारी पूंजी है। इसका क्षय होने लगता है जब भी विकास में वृध्दि होती है। हम सबका दायित्व है कि प्राकृतिक पूंजी अक्षुण्ण बनी रहे। भूमि का उपयोग कृषी के लिए मर्जी के अनुसार हो रहा है। वर्ष भर में ही अनेक फसले लेने की विज्ञान सम्मत पध्दति का निश्चिंतता से प्रयोग हो रहा है। इससे भूमि की गुणवत्ता खराब होगी और उत्पादकता में कमी तो निश्चित ही होगी। तीव्र औद्योगिकरण का दुष्परिणाम होता है, वायू प्रदुषण और जल प्रदूषण के रुप में। परिवहन के साधनों में मोटरसाईकील—स्कूटर और कारों की संख्या में बेताहाशा वृध्दि हूयी है, नतीजा है वायू प्रदूषण। इतना अधिक प्रदूषण हो रहा है कि मानवीय जीवन को खतरा बन गया है। जनसंख्या में निरंतर वृध्दि ने पेडों और जंगलो को काटकाटकर मानव बस्तियॉ

फैलते जा रही है। कुल मिला कर आर्थिक विकास पर्यावरण के लिए सबसे बडा संकट बन गया है। पर्यावरण का संकट भावी पीढी के जीवन का संकट बनेगा ।

वर्तमान पीढी और भविष्य की पीढीयों के जीवन की गुणवत्ता पर दूष्परिणाम बढ रहा है। क्या वर्तमान विकास के कारण भविष्य में विकास की राह अवरुध्द करना उचित है? क्या वर्तमान पीढी की खूशहाली, भावी पीढी के बदहाली की किमत पर होगी? इस तरह के प्रश्न निर्माण हुए है जिन पर गंभीर चिंतन और शीघ्र कारवाई की आवश्यकता है। पिछली या वर्तमान पीढीयों के कारण भावी पीढी को विकास, आनंद के अवसर और स्वास्थ्य पूर्ण जीवन से चूकना पडेगा। वर्तमान पीढी का यह दायित्व है कि जो विकास की राह पर चल रहे है वो विकास निरंतर बना रहे। यह दायित्व और आश्वासन ही शाश्वत विकास का आधार है। प्राकृतिक पूंजी तथा भौतिक पूंजी के संरक्षण की भी आवश्यकता है ताकि भावी पीढी कम से कम इतना प्राप्त करे जितना कि वर्तमान पीढी ने भुतकालीन पीढी से प्राप्त किया है ।

शाश्वत विकास :—

अवधारणा :— शाश्वत विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन १९८० में ''प्रकृति और प्राकृतिक साधनों के सरंक्षण'' के लिए आतंरराष्ट्रीय संघ में प्रस्तुत किया गया। सन १९८७ में ''वैश्विक पर्यावरण व विकास आयोग द्वारा प्रकाशित 'अपना सार्वजनिक भविष्य' इस रिपोर्ट से विश्व के समक्ष शाश्वत विकास यह संकल्पना प्रस्तुत हुयी।

ब्रुटलैंड आयोग की परिभाषा के अनुसार ''शाश्वत विकास वर्तमान की आवश्यकतांओं के लिए होता है, परंतू इसके लिए भावी पीढीयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता से किसी भी प्रकार का समझौता नही करना है''

शाश्वत का सरल अर्थ है ''टिकाऊ तथा विकास से आशय है — वृध्दि होना, सुधार होना, विस्तार होना, कुछ है जो अधिक फलदायी हो रहा है।''

शाश्वत विकास के उद्देश :—

आर्थिक विकास के नए मापदंडो को निर्माण करके उसके द्वारा दरिद्रता का पूर्णत: उन्मूलन करना तथा जनसामान्य की अपेक्षाएँ पूर्ण हो सके, ऐसी परिस्थिती निर्माण करना ।

- उपलब्ध साधन—सामुग्री में गरीब व दूर्बल लोगों को उचित हिस्सा सुनिश्चित करना।

- संपूर्ण व्यवस्था द्वारा निर्मित लाभ का समान वितरण होने के लिए निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों का प्रभावपूर्ण सहभाग बढाकर राजनैतिक व्यवस्था उभारना ।
- आंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्णय लोकतांत्रिक रुप से हो ।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि शाश्वत विकास वह है जो कुछ वर्षो तक सीमित न होकर लोककल्याण के लिए अनेकों पीढीयों तक बढाया जा सके। विशिष्ट समुदायों तक सीमित न होकर संपूर्ण मान जाति के लिए लाभदायक हो। यही सच्चा विकास है ।

शाश्वत विकास एक प्रक्रिया है जो वर्तमान पीढी की आवश्यता को पूर्ण करती है किंतू भावी पीढी की आवश्यकताओं में कोई बाधा अथवा हानि नही पहूचाती। यह प्रक्रिया वर्तमान और भावी पीढीयों की क्षमताओं का श्रेष्ठ उपयोग करने की क्षमता निर्माण करती है। शाश्वत विकास की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि आनेवाली पीढी को उन सभी सूखों के आनंद लेने का अवसर प्राप्त हो जिसका आनंद वर्तमान पीढी ले रही है ।

शाश्वत विकास की शर्ते :—

१) अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल तक वास्तविक विकास हो। प्रतिव्यक्ति आय में वृध्दि हो। लोगों के आर्थिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में वृध्दि हो ।
२) ग्रामीण विकास का उद्देश पूर्ण हो ।
३) उद्योगों के कारण बढता हुआ प्रदुषण कम हो ।
४) कृषी प्रदुषण मूक्त हो ।
५) नैसर्गिक संसाधनों की उपलब्धता को पूंजी मानकर उसका संरक्षण हो ।
६) प्राकृतिक पूंजी भंडार का मापन हो ।
७) हरित लेखाकंन हो ।
८) पर्यावरण मूल्यों का माप हो।

भारत और शाश्वत विकास के समक्ष चूनौतियॉ :—

१) भारत की जनसंख्या की स्थिति और उसमें वृध्दि गंभीर चिंतनीय है। दूनिया की सबसे अधिक दूसरे नंबर की १ अरब ३० करोड जनसंख्या बडी चूनौति है ।
२) वर्तमान में लगभग २५ करोड व्यक्ति निर्धनता रेखा / सीमा से बाहर हुए है पर देश में गरीबी की समस्या विकराल है ।
३) प्राकृतिक संपदा (खनन से प्राप्त) का लगातार विदोहन उसके स्टॉक को कम कर रहा है ।

४) आय, धर्म—जाति, वर्ग आधारित असमानता में वृध्दि हो रही है ।
५) देश के आंतरिक मतभेद—संघर्ष भी एक समस्या है ।
६) जल जीवन है। शहरो—गावों — कस्बों में पीने के पानी का अभाव, भूगर्भ जल स्तर में चिंतनीय गिरावट, कृषि—उद्योगों आदि के लिए पानी की कम उपलब्धता, झीलों—तालाबों में सिकुडता पानी, नदीयों में प्रदुषित जल, मरती नदीयॉ जैसी गंभीर समस्याएँ विद्यमान है ।
७) जंगल विनाश के कारण १/५ भाग समाप्त हो चूका है ।
८) पिछले कुछ ही दशकों में २० लाख हेक्टर भूमि बंजर हो चूकी है। अनेक राज्यों और क्षेत्रों की कृषी भूमि की उत्पादन क्षमता कम हुयी है ।
९) वायू प्रदुषण का स्तर बहूत बढ गया है, विशेषत: कई नगरो और महानगरों की वायू विषैली हो गयी है ।
१०) जैव विविधता लूप्त हो रही है ।
११) तालाब—नदीयों—समुद्र की मछलियों की संख्या कम हो रही है ।
१२) उपलब्ध मानव संसाधन का विकास उपेक्षित है। बेरोजगारी सबसे बडा संकट बन गया है ।
१३) उर्जा के पारंपारिक संसाधन समापन की ओर है ।
१४) भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि में अनेक समस्याएँ दिखाई देती है ।
१५) जलवायू परिवर्तन के अनेक लक्षण व दूष्परिणाम दिखाई दे रहे है ।
१६) नागरिकों के जीवन स्तर में वृध्दि की गति धीमी है ।
१७) संपत्ति के समान वितरण की समस्यॉ बढती जा रही है ।

समस्यॉ का समाधान :—

१) जनसंख्या नियंत्रण शाश्वत विकास का प्रमूख उद्देश है। भारत की विशाल जनसंख्या विकास के मार्ग में बाधा है। इतनी बडी जनसंख्यॉ की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी दूभर कार्य है। इस पर नियत्रंण के लिए कडे सरकारी कानून और सामाजिक जनजागृति जरुरी है ।

२) गरीबी निर्मुलन करना सरकार का दायित्व है किंतू गरीबी हटाना एक राजनैतिक—चूनावी नारा बन कर रह गया है। कृषि आधारित सहायक उद्योग, कृषी विकास, उद्योग विकास, आदि क्षेत्रों के लिए सरकार को कारगर नीतियॉ बनाना और उसे सफलता से सपंन्न कराना आवश्यक है। रोजगार के अधिकाधिक अवसर

निर्माण होने चाहिए। वर्तमान में इसके विपरित स्थिति दिखाई देती है। रोजगार सृजन और प्रतिव्यक्ति आय में वृध्दि करने के प्रयास करने होगे। शाश्वत विकास की संपल्पना और उद्देश में गरीबी निर्मुलन हेतू देश के सभी क्षेत्रों और पक्षों की साझा जिम्मेदारी है।

३) कोयला, मैग्नीज, अभ्रक, तांगा, लोहा, पीतल, तेल, गैस हमारी बहूमूल्य संपदा है। यह हमें प्राकृतिक रुप से प्राप्त हुयी है। ये हमारी प्राकृतिक पूंजी है। भावी पीढी के लिए इसे बचाना जरुरी है। इन धातूओं के उपयोग से बनने वाली वस्तूओं के लिए निर्माण के विकल्प खोजना जरुरी है। इनका आदर्श और विवेकपूर्ण, अनुकूलतम उपयोग ही इन्हे संरक्षित रख सकता है।

४) शाश्वत विकास की अवधारणा तभी पूर्णत: व्यावहारिक रुप से सफल हो सकती है जब भारत में विद्यमान असमानताएँ समाप्त होगी। अमीर—गरीब वर्गीय असमानता, धर्मान्धता के कारण धार्मिक असमानता, जाति—जाति में अंतर एवं उच्च व निम्न जातिगत रचना के कारण निंदनीय असमानता, भाषा के आधार पर भेदभाव, जैसी विभिन्न असमानताएँ मानव जाति को छिन्नभिन्न कर राष्ट्रीय एकता को विघटीत करती है। देश के नागरिकों का मनोविज्ञान समझ कर उनकी मानसिकता में परिवर्तन करके ही असमानताओं के विचार को नष्ट किया जा सकता है। इनके उच्चाटन के लिए कानून का कडा अनूपालन आवश्यक है। अमीर और गरीब के बीच का बढता अंतर आर्थिक विषमता को बढा रहा है। इसके लिए सरकारी स्तर पर आर्थिक उपायों को लागू करना ही होगा।

५) देश के अंतर्गत—आंतरिक संघर्ष भी शाश्वत विकास के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करने में बाधा है। आतंकवाद, नक्सलवाद उत्तर—पूर्वी राज्यों के निवासियों की मॉगें एवं असंतोष, कश्मीर समस्यॉ, अनेक राज्यों के मध्य नदीयों को लेकर संघर्ष, बेरोजगारी के कारण युवा असंतोष, अमीर—गरीब संघर्ष, आदि अनेक समस्याएँ मूँह उठाये खडी है। वर्तमान समय में ही ऐसे संघर्षो को विराम लगाने के उपाय और समाधान खोजना जरुरी है। जिन राजकीय दलों और सरकारों से इसके निराकरण हेतू कदम उठाने की अपेक्षा रहती है वे ही अपने राजनैतिक स्वार्थ और चूनावी लाभ के लिए इन्हे या तो उपेक्षित रखते है या इन्हें हवा देते है। ये पूरा वातावरण बदलना ही पडेगा ।

६) भारत में प्रतिवर्ष लगभग ४०० दसलाख हेक्टर मिटर वर्षा का पानी बरसता है। इसकी बूंद—बूंद भूमि के भीतर सोखने की व्यवस्था तथा जल संग्रहण की व्यवस्था करना हमारा प्रामि दायित्व है। जल जीवन है — यह एक नारा नही बल्कि एक वास्तविकता है। क्या इस सरकारी—गैरसरकारी संस्थाएँ एवं नागरिक समझ रहे है। नदी जोडना योजना, जल व्यवस्थापन, दुरुपयोग रोकथाम, तालाबो—झीलो—जलाशयों की देखरेख एवं सुरक्षित करना, ऐसे ही हजारों का निर्माण करना, पानी रोकने के उपाय, छोटे बांधों नहरों का निर्माण एवं उचित उपयोग, जल प्रदुषण रोकना, गंगा सफाई जैसी सभी नदियों के लिए योजनाएँ एवं पर्याप्त धनराशी की व्यवस्था करना, जनजागृति कार्यक्रम, उद्योगों के लिए पानी का पूर्नउपयोग, समुद्र किनारों का स्वच्छ रखना, समूद्र में गंदे पानी को बहाने से पहले उपचार, कृषि के लिए आवश्यकता के अनूरुप ही पानी का उपयोग जैसे उपायों को गंभीरता से लागू करना होगा।

७) वन वरदान है। भारत में कूल ७८ लाख २९ हजार हेक्टर क्षेत्र वनाच्छादित है। कूल भूमि का २३.८१ प्रतिशत वर्ग हेक्टर वन क्षेत्र कम हुआ है। देश के आर्थिक विकास के नाम पर वनकटाई तथा भूभाग के पेडों की अंधधूंद कटाई चल रही है। वन एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर लोक सहभाग, जन जागृति के साथ सरकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं को कडाई से लागू करने की अपेक्षा है। वन बचेंगे तो जीवन बचेंगें। पर्यावरण तज्ञ सुनीता नारायण के अनुसार ‘‘वनों का आर्थिक मूल्य शीघ्र निश्चित करके देश की अर्थव्यवस्था में इसे सम्मिलित करना चाहिए। वनों के सभी पोडें की किंमत निश्चित करके उतनी ही निधि का प्रावधान किया जाये, जो इनका संवर्धन करते हो। इससे लोंग वनवंवर्धन के लिए अधिक आस्थापूर्वक प्रयत्न करेंगे। जो वनभूमि शेष बची है, उसकी उत्पादकता बढाने का प्रयास करना चाहिए। वन सवंर्धन के लिए नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता है ।’’ सरकारी वनविभाग के उदासीन और भ्रष्ट आचरण पर सख्त प्रतिबंध आवश्यक है। किसी भी देश में उसके कूल भूभाग का ३३ टक्के प्रतिशत भाग वनाच्छाति होना चाहिए। भारत ने भी इस लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। तभी शाश्वत विकास की अवधारणा को सफल किया जा सकेगा। शहरों — गावों में पौधारोपण केवल फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम न बने ।

८) कृषिभूमि का बंजर होने का कारण भूमि पर अविवेकपूर्ण, अवैज्ञानिक एवं अप्राकृतिक रुप से उपयोग करना है। भूमि की उर्वरता कायम रखने के लिए मिट्टी

की गुणवत्ता के अनूसार फसल पध्दति अपनाना होगा। रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद व सेंद्रिय खाद, उत्तम बीज, किटनाशकों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना होगा। भारत के कृषि विद्यपीठों ने भूमि को दीर्घकाल तक उर्वर बनाए रखने के लिए निरंतर संशोधन करके उसके लाभ उसे सरकार की सहायता से सामान्य किसानों तक पहूचाने की आवश्यकता है ।

९) तालाबों—नदीयो एवं् समुद्र को मनूष्य द्वारा प्रदूषित करने का अबाध सिलसिला चल पडा है। इसे जल — जीवों के जीवन और अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जल प्रदूषण को रोककर मतस्य उद्योग को बचाना आवश्यक है। भारत में उपजिविका के व्यवसाय के रुप में तथा आहार के रुप में मत्स्य और तत्सम व्यवसाय से बहुत आर्थिक संभावनाएँ है, अत: मछलियों का जीवन बचाने हेतू जल प्रदुषण को समाप्त करने के लिए सरकार को जनसहभाग से कठोर कदम उठाने होंगें ।

१०) बढते औद्योगिकरण, वाहनों से निकलने वाला धुआ, खेतों से निकलने वाली पराली जलाने, अपशिष्ट पदार्थो को जलाने आदि के कारण शहरों और गावों में वायू प्रदूषण गढ गया है। लोगों के लिए ये जहरीली वायू जीवन के लिए खतरा बन गयी है। इसके कारण होने वाली मौतो का प्रमाण भी बढ गया है। इसके लिए सिर्फ कठोर कानून, सरकारी ईच्छाशक्ति और लोकसहभाग ही एकमात्र विकल्प है ।

११) वायू, जल, वन, भूमि आदि समन्वित साफ सूथरा पर्यावरण ही जैव विविधता संरक्षण के लिये उपयोगी है। उपरोक्त उल्लेखित इन उपायों का संयूक्त प्रयोग करना पडेगा।

१२) वर्तमान समय में मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता है। भारत में बडी संख्या में उपलब्ध मानव संसाधन का योग्य उपयोग करना चाहिए। इसके लिए शालेय, महाविद्यालय, विद्यापीठों का दर्जा बढाना पडेगा, प्रशिक्षण देने के लिए कौशल्य विकास के लिए अनेक संस्थानों की आवश्यकताहै। उपक्रमों में कर्मचारिओं के लिए अच्छी कार्यदशाओं, वेतन, पदोन्नति के अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है— नए—नए रोजगार के अवसरों का निर्माण, मानव संसाधन का

विकास और उन्हे उचित स्थान पर रोजगार दिया जाना आवश्यक है। बेरोजगारी की समस्यॉ मानव संसाधनों के उपेक्षा और दुरुपयोग का लक्षण है ।

१३) अब देश में अपना ध्यान अपारंपारिक उर्जा की ओर मोडना चाहिए। देश को प्राप्त प्रखर सूर्यप्रकाश, सतत बहनेवाली हवाएँ, वनस्पतियॉ, बायोगॉस, समुद्र किनारे की शक्तिशाली हवाएँ आदि से उर्जा प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए। गॉव के स्तर पर ही समूह में उर्जा निर्माण हो। इथेनॅल, प्राकृतिक वनस्पति से बनी मिथेन गॅस, बायोगैस जैसे उर्जा के पर्यायी साधनों का प्रचार और प्रकल्पों की संख्या में वृध्दि करना चाहिए — उर्जा ही बचत भी उर्जा निर्माण ही है ।

१४) मानव द्वारा पर्यावरण से की गई छेडछाड के कारण जलवायू परिवर्तन के अनेक लक्षण और दुष्परिणाम आज देश के विभिन्न भागों में दिखाई दे रहे है। समुद्र का बढता जलस्तर, बर्फीले पहाडों का पिघलना, असमय वर्षा—ठंड—उष्णता, पृथ्वी का तापमान बढना, हिमस्खलन, सूखा, वर्षा की कमी आदि लक्षण जलवायू, परिवर्तन से संबधित है। उपरोक्त सभी उपायों से जलवायू परिवर्तन के दुष्परिणाम कम होंगें ।

१५) शाश्वत विकास का महत्वपूर्ण संकेताक है नागरिकों के जीवन स्तर में वृध्दि। अत: देश के विकास में सामान्य नागरिको का पर्याप्त और उचित हिस्सा देना ही नागरिको के जीवन स्तर में वृध्दि कर सकता है। आवश्यकताओं की वस्तु की गुणवत्ता तथा उत्पादन की मात्रा मं वृध्दि तथा उचित मूल्य जीवन स्तर में वृध्दि करेंगे ।

१६) आर्थिक वृध्दि और विकास के सतत शाश्वत रहने का एक संकेतांक है — संपत्ति का समान वितरण। सरकार की ईच्छाशक्ति और उचित आर्थिक नितियॉ ही संपत्ति के वितरण की असमानता को कम कर सकती है ।

निष्कर्ष :—

शाश्वत विकास की अवधारणा केवल आर्थिक अध्ययन का विषय नही है। यह संपूर्ण पर्यावरण और संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित करती है। आज भारत में आर्थिक वृध्दि और आर्थिक विकास होता दिखाई देता तो है किंतू इसे हम शाश्वत विकास नही कह सकते। केवल वर्तमान काल और वर्तमान पीढी की आवश्यकताओं

की पूर्ति, वर्तमान पीढी की आवश्यकताओं की पूर्ति, अवसर, आनंद, उपभोग तक ही सिमित न होकर अनंत काल तक इसका हस्तातंरण होना चाहिए। शाश्वत विकास के समक्ष चूनौतियों का सामना करने और इसे निरंतर बनाए रखने के लिए सरकारों, प्रशासन, संस्थाओं, राजकीय दलों, एन. जी. ओ., तथा प्रत्येक व्यक्ति को जागरुक होकर प्रयत्न करने पडेंगें। यह संपूर्ण देश और देश के नागरिकों का सामूहिक दायित्व है। पर्यावरण रक्षण को जन आंदोलन बनाना होगा ।

संदर्भ सूची :—

१) समृहर भारत, वनराई, विशेषांक २०१३
२) https;//en.m.wikipedia.org
३) https;//www.undp.org
४) www.sd-commission, org.uk
५) www.economicdiscussion.net
६) idiaenvironment portal.org.in
७) पुरी, वी. के., मिश्र एस. के. भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस
८) Singh, R.B. Thakur D. K.,Nema A.K., Environmal studies, Ramesh Depot.
९) भाटीया सुदर्शन, प्रदूषण मूक्त धरती, अनंत साहित्य प्रकाशन, दिल्ली.